

बना दिया जाए या उत्तरांचल कर दिया जाए, यह अलग व्यवस्था है। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया था जो केन्द्रीय सरकार के पास विचाराधीन है। केन्द्रीय सरकार ने स्वयं इस संबंध में कुछ सूचनाएं प्रदेश सरकार से मांगी थी और भेरी जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पत्र दिनांक 27 दिसम्बर, 1991 का जवाब 4 मार्च, 1992 को जितनी भी सूचनाएं थी भारत सरकार को उपलब्ध करने का दी है। लेकिन यह क्षेत्र अलग यह एक अलग प्रश्न है। इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए और इस प्रदेश के इस क्षेत्र में जो गरीबी है, जो लोगों का असंतोष है उसको दूर करने के लिए भारत सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अपेक्षा करता हूँ कि वह इस संबंध में शीघ्र ही कदम उठावगी जिससे कम से कम इस क्षेत्र लोग अपने को उपेक्षित महसूस न करें।

श्री संघ प्रिय मौलम (उत्तर प्रदेश) :
मैं आदरणीय श्री सत्य प्रकाश मालवीय जी के विचारों से सहमति व्यक्त करते हुए एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में जो तराई का क्षेत्र है आज तक वहाँ भूमि सुधार नहीं हुआ और एक ओर गरीब और भूमिहीन खेतिहर मजदूर शोषण में रह रहे हैं और दूसरी तरफ हजारों-हजार एकड़ के फार्म एक-एक व्यक्ति के पास हैं। एक तो भूमि सुधार होना चाहिए और दूसरे टिहरी बांध जो खटाई में पड़ा हुआ है और जो प्रोसेसिंग इकाई में ला सकता है वह टिहरी डैम राजनीतिक कारणों की वजह से पड़ा हुआ है उसका निर्माण होना चाहिए ताकि इस क्षेत्र का विकास हो सके।

Likely closure of Barauni oil refinery due to financial constraints

श्री शंकर दयाल सिंह (बिहार) :
उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा जो आज विशेष लोक महत्व का विषय है वह बिहार के बरोनी ऑयल रिफाइनरी की जो वर्तमान स्थिति है उससे सम्बन्धित है। बिहार में

पब्लिक सेक्टर के अन्तर्गत इस समय जो मुख्य रूप से उपक्रम कार्यरत हैं उनमें से सिंदरी, बरोनी, बोकारो, हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची और कोल इंडिया के जो उपक्रम हैं मुख्य रूप से माने जाते हैं। इसमें सिंदरी फर्टीलाइजर कारपोरेशन और बरोनी ऑयल रिफाइनरी ऐसे उपक्रम हैं जिनके ऊपर प्रश्नचिह्न लगा हुआ है। विगत कई वर्षों से ये घाट में चल रहे हैं और घाट में चलने के कारण सरकार को जहाँ एक ओर इन पर अधिक ध्यान देना चाहिए वहाँ सरकार अधिक तो क्या पूरा भी ध्यान नहीं दे रही है जिसके कारण ये दोनों उपक्रम बराबर बंद होने के क्रम में रहते हैं। मुख्य रूप से इसका कारण यह है कि सिंदरी को यहाँ माडर्नइजेशन के लिए फंड मिलना चाहिए वहाँ दूसरे-दूसरे फर्टीलाइजर कारपोरेशन को तो मिले लेकिन सिंदरी में भारत सरकार ने कोई पैसा इन्वस्ट नहीं किया और दूसरे ओर बरोनी ऑयल रिफाइनरी जिसके बारे में मुख्य रूप से मैं सवाल उठा रहा हूँ जिसकी क्षमता 4 मिलियन टन कूड ऑयल शोधन की है। 4 मिलियन टन कूड ऑयल शोधन की क्षमता वह रिफाइनरी को इस समय केवल 2 मिलियन टन कूड ऑयल मिलता है, मतलब आधा। वह भी कभी-कभी नहीं मिलता यानी उसमें कम मिलता है। इसका मुख्य कारण यह है जिस समय यह उपक्रम बना था देश में इस तरह के उपक्रम बहुत कम थे। देश में उस समय जब इसका निर्माण हुआ था तो लोगों की आशा बंधी थी दो कारणों से। एक तो पूर्वांचल प्रमम से कूड ऑयल वहाँ आना था जिसकी वजह से उसकी सप्लाय हर जगह होती थी। उस समय देश में बहुत जगहों में हमारे परिशोधन कारखाने नहीं थे। दूसरी बात यह है कि बिहार का जो बहुत बड़ा हिस्सा उत्तर बिहार में रहता है उसमें बेरोजगारी को दूर करने के लिए और उसका विकास करने के लिए, उसकी समृद्धि के लिए बरोनी ऑयल रिफाइनरी का निर्माण हुआ था। हमारे मित्र श्री अहलुवालिया जी वहीं के रहने वाले हैं, वहीं रहते हैं। वह अच्छी तरह से इस समस्याओं को जानते हैं।

2:00 P.M.

लेकिन मैं आपसे इस संबंध में जो अपील करना चाहता हूँ वह यह है कि अभी आसाम में प्रधान मंत्री जी ने जाकर, पहले से तो वहाँ था ही, लेकिन फिर अभी जाकर प्रधान मंत्री ने एक नई रिफायनरी की स्थापना के लिए गिलान्यास किया है। उसके होने के बाद संभव है कि यह भी मिले और यह बंद कर दिया जाए : वही इसको लेकर बराबर लोगों के अन्दर चिन्ता व्याप्त है और नूँक हजारों लोग रोजगारी के शिकार हो जाएंगे, इसलिए उनमें चिन्ता व्याप्त है। मैं सरकार से एक बात इस संबंध में बड़े ही विनय के साथ कहना चाहूँगा कि एक्स्पेंस की पालिसी क्या है, यज्ञे यह बात समझ में नहीं आती है और बहुत चिन्ता व्याप्त है। परतांगे उपक्रम चलने भी हैं, माहे मुख्य के हैं, उनका प्रोडक्शन भी अच्छा हुआ है, लाभ भी अच्छा हुआ है, जिसकी सहायता भी अच्छी है, उनको एक्स्पेंस न दे करके सरकार चाहती है कि उनको बंद करके प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जाय। पब्लिक सेक्टर को किसी तरह से बदनाम करके प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जाय। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। सरकार की प्राइवेट ग्रान् प्रोडक्शन की एक फ़ैक्ट्री भारत सरकार की ओर से मिली है, उसके केवल एक पैरा को, लास्ट पैरा को, बंद कर सुनाया चाहता हूँ—

"The Government is also pending up the expansion of exiting refineries and the setting up of new refineries in the private, point and public sectors. The capacity of existing refineries is planned to be increased by 7.5 million tonnes. Also, new refineries are being set up all Mangalor, Kamal and Numaligairh. In addition, three more grassroot refineries in the Eastern, Central and Western parts of the country are to be implemented with maximum speed. The new policy facilities establishment of refineries in the joint sector who will raise their own foreign exchange and rupee resource."

उपसभाध्यक्ष जी, इसके साथ ही मैं भारत सरकार से यह अपील भी करना चाहता हूँ कि उसके पास जब बरोनी आयल रिफ़ाइनरी जैसी तेल शोधक कारखाना है जिसकी क्षमता इतनी बड़ी है कि चार मिलियन टन कूड आयल का शोधक वहाँ पर किया जा सकता है और बहुत ही मॉडर्न ढंग से यह तयार किया गया है, उसके प्रति इस तरह की उम्मेदा नीति रखकर नई आयल रिफ़ाइनरी खोलने के लिए और प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए और उनके लिए फ़ौरन एक्स्पेंस प्राप्त करने के लिए सरकार क्यों प्रयास कर रही है? इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार इस संबंध में एक बयान पूरे तौर पर दे और तत्काल बरोनी आयल रिफ़ाइनरी को जो क्षमता है चार मिलियन टन कूड आयल की, जिसमें उसको दो मिलियन टन कूड आयल हो मिल रहा है, वह पूरा उसको चार मिलियन टन कूड आयल मिले जिससे उसकी क्षमता के अनुसार प्रोडक्शन हो और लोगों को काम भी मिले।

श्री एस० एस० ग्रहभक्तिया (बिहार उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं श्री शंकर दयाल सिंह जी द्वारा उठाये गये विशेष उल्लेख का पूरा समर्थन करते हुए आप के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि बरोनी आयल रिफ़ाइनरी जो आसाम कूड पर बंध करके बनाई गई थी और इसे जो भी कूड मिल रहा था, जब आसाम का आन्दोलन चल रहा था तो कम मिल रहा था, लेकिन आज इसकी बड़ी क्षीण अवस्था इस कम्पनी की हो गई है। सारी तकनीक उपलब्ध है, मशीनरी उपलब्ध है, जगह उपलब्ध है, लेकिन कूड आयल नहीं मिलता है जिसको यह प्रोसेस कर सके। इस संदर्भ में एक प्रोज़ेक्ट बनाया गया था कि हल्दिया में जो पाइप लाइन आती है, जिसमें कुछ फ़िक्स्ड प्रोडक्ट्स भी पम्प किये जाते हैं, इड तरफ लाई जाय जो यू०पी० की तरफ जाती है और बरोनी होकर आती यह मेरी भांग है। हल्दिया से कूड पाक लाइन दी जाय, कूड आयल सप्ल है

पाइल लाइव ली जाय। हल्दिया में जो रिफाइनरी चल रही है वह पूरी की पूरी फार; कूड आयल पर डिपेन्ड करती है। इसलिए अगर इम्पोर्टेड कूड आयल पम्प करके बरौनी भेजा जाय तो मैं समझता हूँ कि जो चार मिलियन टन की उसकी कैपेसिटी है उसका पूरा यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। अन्यथा जो अवस्था है, वहाँ बरौनी थर्मल पावर स्टेशन वही फरनिश शायल लेकर चलता है, जसा कि आपके ज्ञात है। बिहार में बिजली की अवस्था बहुत खराब है और बरौनी थर्मल पावर स्टेशन को अगर फॉल्स आयल न मिला तो वह भी बंद हो जायेगा। इसके साथ ही वहाँ जो हिन्दुस्तान फटिलाइजर कारपोरेशन की फटिलाइजर यूनिट है वह इस आयल रिफाइनरी में नेपथा लेती है, जो उसका रा-मेटी रियल है। उसे भी अगर नेपथा नहीं मिलेगा तो वह कारखाना बंद हो जायेगा। इस कारखाने के कमजोर हो जाने से, रुग्ण हो जाने में और भी जितनी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज वहाँ है वे रुग्ण हो चुकी है। अगर आप इस इलाके का दौरा करें तो पायेंगे कि उस इलाके में गकड़ा स्माल स्केल इंडस्ट्रीज है जो बरौनी आयल रिफाइनरी, हिन्दुस्तान फटिलाइजर और बरौनी थर्मल पावर स्टेशन को कटर करने के लिये चलती हैं। इन सब की अवस्था खराब है। मझे ज्ञात है कि हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इसका एग्जोरेंस दिया था और उस इलाके में एक पेट्रो-कैमिकल कंप्लेक्स लगाने का यत्न किया था। पर आज तक वह अनुमोदन पर हमारे पेट्रोलियम विभाग में पड़ा हुआ है, आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। वहाँ के लोग, जिन इलाके का संवर्धन आपके बनाया गया था कि यह जमीन एक्वायर होगी, उस जमीन के बारे में, उस जमीन के मालिक आज तक इंतजार कर रहे हैं कि कब यह जमीन एक्वायर होगी और कब यह पेट्रो-कैमिकल कंप्लेक्स बनेगा। पेरी मांग है कि सिर्फ बरौनी आयल रिफाइनरी के लिये फार्गेन कूड लेने की ही आप व्यवस्था न ही करेंगे बल्कि वहाँ पर

पेट्रो-कैमिकल कंप्लेक्स, जिसके लिये हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने वचन दिया था, उसके निर्माण में। यही कहते हैं मैं इस बात का समर्थन करता

THE VICE-CHAIRMAN SHRI SYED SIBTEY RAZI: Shri Kaatal Morarka
Not present.

SHRI MENTAY PADMANABHAM (Andhra Pradesh); Sir, may I seek some clarification? According to this Revised List of Business, the Private Members' Business would start at 2 o'clock.

THE VICE CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI): No. It is at 2.30 p.m.

SHRI PASUMPON THA.
KIRUTTT-
NAN (Tamil Nadu): 2 o'clock.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI): It is at 2.30 p.m. I think it is a printing mistake. It has been our convention that we take up the Private Members' Business at 2.30 p.m. 'TODAY also, we will take it up at that

SHRI MENTAY PADMANABHAM;
Can you finish all the special mentions before that?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI): I am trying to finish them. Shrimali Jayanthi Natarajan. Not present,

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM; Mr Vice-Chairman, in Hindi it is printed as 20.30".

THE VICE CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI): As I told you, it is a printing mistake. The Secretariat also has informed me that it is a printing mistake. I am sorry for the inconvenience caused to hon. Members. Shri Mentay Padmanabham.

Impending changes in Textbooks used in total literacy programme by Andhra Pradesh Government